USHA KUMARI
Guest Asstt. Professor,
Deptt. of Economics,
Vaishali Mahila College, Hajipur.

Date: 23-05-2020
Page: (4)

Part I (Hons.)
Paper II (Fiscal Policy to control Inflation)

(a) प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)

प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस पर वह वैधानिक रूप से लगाया जाता है। अर्थात, जिस कर का दबाव (Impact) तथा भार (Incidence) एक ही व्यक्ति पर पड़ता है और जिसे दूसरे पर टाला नहीं जा सके, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसमें आते हैं - आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर आदि।

(b) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes)

जब कर के भार को दूसरों पर टाला जा सके अथवा यदि कर का दबाव (Impact) एवं भार (Incidence) अलग-अलग व्यक्तियों पर पड़े तो इस प्रकार के कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसमें आते हैं — बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा कर आदि।

(ii) सार्वजनिक ऋण (Public Debt or Borrowing):

ऋण सरकार की आय का विशेष स्रोत है। जब सरकार अपने देश या विदेशों से ऋण लेती है तो उसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं।

(iii) ~~राजकोषीय घाटा (Deficit Financing)~~
घाटे की वित्त-व्यवस्था (Deficit Financing)

Fiscal Measures to correct the inflationary situation

अतिरेक मांग अथवा स्फीतिकारी अंतराल (Inflation) को दूर करने के लिए राजकोषीय नीतियों का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है —

(1) करों में वृद्धि :

करों में वृद्धि करके स्फीति को रोका जा सकता है। करों की वृद्धि के प्रमुख दो उद्देश्य होने चाहिए। प्रथम, कर इस प्रकार लगाये जाने चाहिए कि अर्थव्यवस्था के संपूर्ण उपभोग-व्यय को कम किया जा सके।

Scanned with CamScanner

द्वितीय, निवेश व्यय में भी वृद्धि नहीं होनी चाहिये।

चूँकि स्फीतिकाल में अर्थव्यवस्था में पूर्ण-रोजगार की स्थिति होने से वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को बढ़ाना कठिन हो जाता है तब मूल्यों को स्थिर रखने का एकमात्र उपाय उपभोग वस्तुओं की मांग को सीमित रखना है। ऐसा तभी संभव है जब जनसाधारण की आय में कमी हो। अतः करों में वृद्धि कर व्यय-योग्य आय (Disposable Income) को कम किया जाता है।

(2) सार्वजनिक व्यय में कमी (Decrease in Govt. Expenditure):

जब मुद्रा अथवा साख स्फीति का प्रभाव हो और वस्तु के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही हो तो मौद्रिक नीति के साथ राजकोषीय नीति का सार्वजनिक व्ययों में कमी लाकर किया जाता है। कम महत्व वाली योजनाओं को स्थगित कर लोगों की क्रय-शक्ति में कमी लाकर स्फीति की अवस्था को समाप्त किया जा सकता है।

(3) सार्वजनिक ऋण में वृद्धि (Increase in Govt. Borrowing):

स्फीति काल में लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है। अतः जनता के पास से अतिरिक्त धनराशि खींचने के लिए सरकार द्वारा एक व्यवस्थित ऋण योजना चालू करनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बचत-पत्र निर्गमित किया जाना चाहिए। साथ ही सामूहिक बचत अभियान या अनिवार्य बचत योजना को लागू कर भी गम्भीर स्फीति की अवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है।

(4) घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी (Reduce Deficit Financing):

घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी अर्थात, नोट निर्गमन में कमी लाकर भी स्फीति की अवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है।

इस प्रकार अर्थव्यवस्था में स्फीति की रोकथाम तथा आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाता है।

Scanned with CamScanner